

( राजस्थान-सरकार )

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 182 / 2022

रजिस्ट्रेशन सं० :- 2022 / 136

### **बउनवान**

1. लटूरलाल पुत्र चतुर्भुज मीणा निवासी अरडाना तहसील अटरू जिला बारों
2. गिर्राज प्रसाद पुत्र रामदयाल मीणा निवासी अरडाना तहसील अटरू जिला बारों

(अपीलांटगण)

### **बनाम**

छीतरलाल पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा निवासी अरडाना तहसील अटरू जिला बारों

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार अटरू के प्रकरण सं० :- 05 / 2020 में पारित आदेश / निर्णय दिनांक

11.04.2022 अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट

उपस्थित :- 1- श्री ओमप्रकाश मेहता अभिभाषक

अपीलांटगण)

2- श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक

(रेस्पोडेन्ट)

### **निर्णय दिनांक 08.07.2022**

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण सं० :- 05 / 2020 में पारित आदेश / निर्णय दिनांक 11.04.2022 से अप्रसन्न होकर विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 06.05.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के पत्रांक 1444 दिनांक 14.06.2022 से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम चरडाना की आराजी खसरा नं० 593 रकबा 0.81 हैक्टे० खसरा नं० 638 रकबा 0.59 हेक्टे० मे से खसरा नं० 638 रकबा 0.59 हेक्टे० पर रेस्पो० द्वारा बेदखल करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय मे कार्यवाही पेश की गई है जिसमे अपीलांटगण की ओर से जवाबदेही करते हुये हाल खसरा नम्बर 638 रकबा 0.59 हेक्टे० के भू-प्रबन्ध विभाग के सेटलमेन्ट के दौरान पूर्व साबिक खसरा नम्बर 495 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा से कायम किये गये है खसरा नं० 495 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा शुरु से ही अपीलांटगण के पिता व दादाजी चतुर्भुज पुत्र गणेशराम के कब्जे काश्त मे जायज अर्सा 80-90 सालो से चला आ रहा है तथा वक्त काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1955 को अपीलांटगण के पिता व दादाजी का कब्जा काश्त था। इसी आधार पर रेस्पो० के पिता नाथूलाल, पांथूलाल पुत्रगण अमरलाल जाति बैरवा निवासी अरडाना द्वारा दिनांक 26.07.1971 को साबिक खसरा नम्बर 495 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा के एवज मे 1000/- रुपये प्राप्त करके पत्र का पंजीयन सबरजिस्ट्रार, अटरू के यहां कराया गया जिसमें गवाह गवाहान के रूप में अमरसिंह, मदनलाल के अंगूठा निशानी व चंदनलाल के दस्तखत हुये है। इस तथ्य को छिपाकर रेस्पो० द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस

पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया। न ही अपीलांटगण के कोई बयान लिये गये और न ही आस-पास के खेत वालों से कोई पूछताछ की गई। अपीलांटगण को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर निर्णय दिनांक 11.04.2022 पारित किया गया है जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अगर किसी के द्वारा जमीन का बेचान किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में धारा 183 (बी) की कार्यवाही नहीं की जा सकती धारा 175 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही ही की जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा न्याय की मंशा को समझने में भारी भूल की है तथा विधि विरुद्ध मनमाना निर्णय दिनांक 11.04.2022 को पारित किया गया है जो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

यह कि अपीलांटगण के पिता व दादाजी चतुर्भुज पुत्र गणेशराम के द्वारा उक्त आराजियात को तोड़ कर काबिल काश्त बनाया है तथा काफी धन व श्रम खर्च किया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1956 के पूर्व ही मृतक चतुर्भुज पुत्र गणेशराम का अपने जीवनकाल तक कब्जा काश्त रहा। उनका देहान्त 30-32 वर्ष पूर्व हो चुका है उसके बाद उसके दोनो पुत्रों अपीलांट क्रम 1 व रेस्पो. क्रम 2 के पिता रामदयाल का कब्जा काश्त रहा है। रामदयाल का देहान्त हो चुका है। उसके हिस्से पर रामदयाल का पुत्र अपीलांट क्रम 2 गिराजप्रसाद काबिज काश्त है। वर्तमान में अपीलांटगण काबिज-काश्त चले आ रहे हैं जिसे बेदखल करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है जबकि रेस्पो0 के पिता नाथूलाल पुत्र अमरलाल के द्वारा व उसके भाई पांथूलाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 26.07.1971 को यह जानते हुये कि मृतक चतुर्भुज पुत्र गणेशराम का दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है इस कारण दोनो भाईयो द्वारा संयुक्त रूप से मृतक चतुर्भुज पुत्र गणेशराम को कब्जे के आधार पर बेचान कर 1000/- रुपये की राशि प्राप्त कर दिनांक 26.07.1971 को सब रजिस्ट्रार, अटरू के समक्ष प्रस्तुत कर गवाहान की उपस्थिति में पंजीयन करवाया गया। इस कारण पांथूलाल या नाथूलाल द्वारा अपने जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की गई। नाथूलाल का देहान्त जायज अर्सा 30 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसके बाद सन् 2020 में उक्त कार्यवाही रेस्पो0 छीतरलाल पुत्र नाथूलाल द्वारा पेश की गई है जबकि छीतरलाल पुत्र नाथूलाल 1/2 हिस्से व सीताबाई पुत्री नाथूलाल 1/2 हिस्से की खातेदारान है। इस कारण सीताबाई पुत्री नाथूलाल को पक्षकार नहीं बनाकर तथ्यों को छिपाकर अपीलांटगण को परेशान करने के उद्देश्य से रेस्पो0 द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा विधि की मंशा को समझने में भूल की है तथा दिनांक 11.04.2022 को गलत तथ्यों पर विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा अपने पक्षसमर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.सी. 1994 पेज नं0 231 कल्याणमल बनाम सुरेन्द्र कुमार जैन प्रस्तुत किए गए। यदि उक्त विक्रय पत्र गलत है तो ऐसी स्थिति में धारा 183 (बी) की कार्यवाही नहीं की जा सकती धारा 175 आर.टी.एक्ट की कार्यवाही ही की जा सकती है, खातेदार द्वारा उक्त आराजी का विक्रय करने के बाद भी उक्त आराजी विक्रेता के खाते में क्यों रही ? अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक भी गवाह/साक्ष्य के बयान आदि नहीं लिये गये हैं। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत रूलिंग रेफरेंस से सम्बन्धित है न कि 183(बी) के प्रकरण से सम्बन्धित है।

अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रकरण संख्या 5/2020 में पारित निर्णय दिनांक 11.4.2022 निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

**रेस्पॉडेन्ट के अभिभाषक** द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू द्वारा 183(बी) आर.टी.एक्ट के विधिक प्रावधानों के अनुसार ही निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। रेस्पॉडेन्ट वर्तमान में उक्त आराजी का खातेदार है। सीताबाई पुत्री नाथूलाल बैरवा को रिलीज हुई डीड की कॉपी लगी हुई है जिससे वो इसकी एनटाईटल नहीं है। प्रकरण में धारा 175 आर.टी.एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती क्योंकि उक्त विक्रय पत्र को 51वर्ष का समय पूर्ण हो गया है। अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर. डी. 2003 पेज नं. 389-394 पेश किए जिसके अनुसार लिमिटेशन 1971 में 03 से 12 वर्ष एवं 1971-1981 में 30 वर्ष है। आर. आर. डी. 1988 पेज नं. 577 के अनुसार 1971 की डीड लिमिटेशन 12वर्ष थी। उक्त विक्रय पत्र को 51वर्ष का समय पूर्ण हो गया है। वर्तमान में हम खातेदार है। यदि कोई दस्तावेज शुरू से ही प्रभावशून्य है तो उस पर विचार किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलान्तरण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

**प्रकरण में उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई।** इस न्यायालय की एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण सं० :- 05/2020 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 11.04.2022 का गहनता से अध्ययन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में किसी भी व्यक्ति की साक्ष्य, बयान आदि नहीं लिये गये हैं। प्रकरण में रेस्पॉ० के पिता नाथूलाल पुत्र अमरलाल व उसके भाई पांथूलाल द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 26.07.1971 को यह जानते हुये कि मृतक चतुर्भुज पुत्र गणेशराम का दिनांक 15.10.1955 से पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है इस कारण दोनो भाईयो द्वारा संयुक्त रूप से मृतक चतुर्भुज पुत्र गणेशराम को कब्जे के आधार पर बेचान कर 1000/- रुपये की राशि प्राप्त कर दिनांक 26.07.1971 को सब रजिस्ट्रार अटरू के समक्ष प्रस्तुत कर गवाहान की उपस्थिति में पंजीयन करवाया गया जिसका कोई विस्तृत उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में नहीं किया गया है। रेस्पॉडेन्ट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर साबित नहीं होते हैं।

**अतः परिणामस्वरूप** अपीलान्तरण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं० 05/2020 में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, अटरू को प्रतिप्रेषित/रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 26.07.1971 की रोशनी में उभयपक्षों को पुनः सुना जाकर प्रकरण में विस्तृत एवं निष्पक्ष जाँच की जावें तदुपरान्त विधिक निर्णय पारित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक **08.07.2022** को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)  
अति० जिला कलक्टर  
बारों